बृहस्पतिवार, 12 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

श्रीलंकाई खिलाड़ी ने पहले दिया अजीब बयान फिर दी ये सफाई

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

Lahore 1947 की रिलीज डेट का एलान!

Page-05

लोकसभा में अमेरिका समझौते पर घमासान:

राहुल गांधी ने कहा—राष्ट्रीय हितों से समझौता

नई दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

लोकसभा में आज अमेरिका के साथ हुए एक अहम समझौते को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने "अमेरिका की शर्तों पर समझौता" कर देश के हितों से समझौता किया है। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कुछ समय के लिए कार्यवाही भी बाधित रही।राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में भारत की संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा और किसानों-छोटे उद्योगों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समझौते में सरकार ने मजबूती से भारत का पक्ष रखने के बजाय बाहरी दबाव में निर्णय लिया। राहुल गांधी ने कहा, "देश को यह जानने का अधिकार है कि इस समझौते की शर्तें क्या हैं और इससे किसे लाभ होगा। अगर यह डील अमेरिकी शर्तों पर हुई है, तो यह बेहद चिंताजनक है।"कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की कि समझौते का पूरा विवरण संसद के पटल पर रखा जाए और इस पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि संसद को विश्वास में लिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस समझौते का असर देश के किसानों, मध्यम वर्ग, लघु एवं मध्यम उद्योगों और युवाओं पर पड़ सकता है। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने आरोपों को "भ्रामक और राजनीतिक" करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करता और यह डील भी देश की आर्थिक प्रगति, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। मंत्री ने कहा, "भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। किसी भी तरह का निर्णय पूरी पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।" सदन में इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी के समर्थन में सरकार से जवाब देने की मांग की, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमेरिका के साथ बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के बीच इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप आने वाले समय में और तेज हो सकते हैं। विपक्ष जहां सरकार से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं सरकार अपने फैसलों को राष्ट्रीय हित में बता रही है।आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी के तेज होने की संभावना है। फिलहाल, अमेरिका समझौते को लेकर उठे सवालों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

कांग्रेस सांसदों के व्यवहार पर किरेन रिजिजू का आरोप, स्पीकर से बदसलूकी का दावा

संसद में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा स्पीकर के साथ अभद्र व्यवहार और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है। रिजिजू ने कहा कि हालिया घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के कई सांसद स्पीकर के चेंबर में पहुंचे और वहां अनुचित आचरण किया।मीडिया से बातचीत में रिजिजू ने दावा किया कि करीब 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी उस समय वहां मौजूद थे और जो कुछ हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। रिजिजू के अनुसार, स्पीकर के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से दोहराया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपराओं और गरिमा के खिलाफ है।रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने सांसदों को उकसा रहे हैं और उनके आचरण को रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं।

तीन कॉरिडोर और 13 स्टेशनों की परियोजना को हरी झंडी

दिल्ली को मिलेगी मेट्रो की नई सौगात:

दिल्ली, टीवी भारतवर्ष

दिल्लीवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को और सुलभ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 13 नए मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नए कॉरिडोर का उद्देश्य शहर के उन इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है जहां अब तक कनेक्टिविटी सीमित रही है। इससे न केवल यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क और अधिक विस्तृत और सुगम हो जाएगा।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर न रहना पड़े।परियोजना की विस्तृत योजना और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और इसे तय समयसीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास रहेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए कॉरिडोर से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापारिक और आवासीय क्षेत्रों को भी नई गति मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के इस विस्तार से राजधानी के परिवहन तंत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। परियोजना के लिए आवश्यक बजट प्रावधान और तकनीकी तैयारियों पर संबंधित विभागों ने काम शुरू कर दिया है। साथ ही, निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजना भी तैयार की जाएगी।

पटना में पुलिस मुठभेड़:

कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या घायल

पटना, टीवी भारतवर्ष

पटना में सोमवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राजीव कुमार उर्फ सूर्या घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान जब टीम ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया।पुलिस ने बताया कि राजीव उर्फ सूर्या पर हत्या, रंगदारी, लूट और अवैध हथियार रखने समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ के बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अपराध पर नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सघन कार्रवाई से स्थानीय अपराध पर काबू पाया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को राजीव या उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में पटना में अपराध की दर में वृद्धि देखी गई थी, और राजीव उर्फ सूर्या जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी से शहर में शांति बहाल करने में मदद मिल सकती है। पुलिस ने कहा कि वह न केवल अपराधियों को दबाने बल्कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लगातार कदम उठा रही है।

₹9.12 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट:

यूपी सरकार ने विकास और निवेश पर लगाया बड़ा दांव

उत्तर प्रदेश, टीवी भारतवर्ष

प्रदेश सरकार ने 9.12 लाख करोड़ का विशाल बजट पेश किया, जिसे राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने इसे प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया है।वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट समावेशी विकास की अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाओं और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।कृषि क्षेत्र के लिए बजट में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। किसानों को तकनीकी सहायता, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा योजनाओं को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और मंडी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकारी स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार पर बल दिया गया है।युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, स्वरोजगार योजनाओं और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गरीब कल्याण योजनाओं के लिए भी बजट में पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है। हालांकि, विपक्ष ने बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीन पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत है। विपक्षी दलों ने रोजगार, महंगाई और किसानों की आय से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 9.12 लाख करोड़ का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किस गति और प्रभावशीलता के साथ होता है।

ट्रेड डील पर भारत की मजबूत पकड़,

व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट में किए बदलाव

व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की फैक्ट शीट में बदलाव किया है। 'दालों' को टैरिफ कटौती सूची से हटाया गया, जिससे भारतीय किसानों को राहत मिली। साथ ही, $500 बिलियन खरीद पर 'कमिटेड' की जगह 'इरादा' शब्द जोड़ा गया, जिससे भारत को आर्थिक और कानूनी लचीलापन मिला।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

नई दिल्ली के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत में, व्हाइट हाउस ने भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील के बाद जारी अपनी फैक्ट शीट में बदलाव किया है। पहले, दालों का ज़िक्र अमेरिकी प्रोडक्ट्स की उस लिस्ट में था जिस पर उसने कहा था कि भारत टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा। हालांकि, अब इस प्रोडक्ट को हटा दिया गया है। संशोधित फैक्ट शीट में दो सबसे प्रमुख बदलाव किए गए हैं जो भारत की संप्रभुता और आर्थिक हितों की सुरक्षा को दर्शाते हैं शुरुआती फैक्ट शीट में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची में 'दालों' (Certain Pulses) का उल्लेख था, जिन पर भारत आयात शुल्क (Tariff) कम या खत्म करने वाला था। अब संशोधित दस्तावेज़ से दालों को पूरी तरह हटा दिया गया है। यह भारत के करोड़ों दलहन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि विदेशी दालों पर शुल्क कम होने से स्थानीय बाजार प्रभावित हो सकता था। पहले दस्तावेज़ में लिखा था कि भारत $500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए "प्रतिबद्ध" (Committed) है। भारत की आपत्ति के बाद, अब इस शब्द को बदलकर "इरादा रखता है" (Intends) कर दिया गया है। यह कानूनी रूप से भारत को अधिक लचीलापन देता है और यह दर्शाता है कि ये खरीद बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी। व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि भारत कई तरह के US इंडस्ट्रियल सामान और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर के दाने, लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। फैक्ट शीट में यह भी बताया गया था कि भारत ने और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है, जिसमें USD 500 बिलियन से ज़्यादा की US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती के सामान, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान है। हालांकि, मंगलवार को जारी फैक्ट शीट के बदले हुए वर्शन में कुछ खास बदलाव किए गए। "कुछ दालों" का ज़िक्र हटा दिया गया, और भारत की खरीद के बारे में भाषा को "कमिटेड" से नरम करके "इरादा" कर दिया गया। 'भारत सभी U S इंडस्ट्रियल सामान और US के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत का इरादा और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और US एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट के $500 बिलियन से ज़्यादा खरीदने का है। भारत सभी US इंडस्ट्रियल सामान और US खाने और खेती के प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत का इरादा और ज़्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदने और U S एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला, और दूसरे प्रोडक्ट के $500 बिलियन से ज़्यादा खरीदने का है," अपडेटेड डॉक्यूमेंट में अब कहा गया है।

पटना एनकाउंटर: 20 मामलों का आरोपी 'सूर्या' पुलिस गिरफ्त में

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बिहार पुलिस ने बुधवार तड़के एक साहसिक ऑपरेशन में पटना के आलमगंज इलाके से कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। सूर्या पर लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कम से कम 20 संगीन मामले दर्ज हैं। पटना (पूर्व) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परिचय कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्या आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट इलाके में किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (STF) की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। उन्होंने कहा, "सूचना मिली थी कि शस्त्र अधिनियम, लूट, डकैती और रंगदारी से जुड़े करीब 20 मामलों में वांछित राजीव कुमार गायघाट स्थित एक स्थान पर छिपा हुआ है। इसके बाद जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम गठित कर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।" पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को देखते ही कुमार ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने नियंत्रित जवाबी गोलीबारी की और उसे काबू में कर लिया। उन्होंने कहा, "कुमार के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है।" पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

शरद पवार की सेहत में सुधार,

जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी

गलवान घाटी में क्या हुआ?

ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने दी बड़ी जानकारी,

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' में कथित रूप से कही गयी बातों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों जोरदार तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जवाब में सत्तारुढ़ भाजपा का कहना है कि नरवणे द्वारा उनकी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशक के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करने से राहुल गांधी बेनकाब हो गए हैं और देश के सामने एक ''काल्पनिक तथ्य'' पेश करने के लिए कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए। देखा जाये तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर संदेह जताते हुए राहुल गांधी इन दिनों जो सवाल उठा रहे हैं उसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया हुआ है। दोनों ओर से नेताओं के बयानों का शोर इतना ज्यादा है कि जनता भी असमंजस में पड़ गयी है और यह जानना चाहती है कि आखिर सच में हुआ क्या था? तो आइये गलवान संघर्ष के दौरान सेक्टर कमांडर रहे ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत के संबोधन के माध्यम से जानते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था और क्या राहुल गांधी का यह आरोप सही है कि भारत ने अपनी जमीन खोई? हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने कहा है कि भारतीय सेना की मजबूत तैयारियों ने ही यह सुनिश्चित किया था कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प एक पूर्ण युद्ध में न तब्दील हो। अपने संबोधन में ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत ने कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प पूर्ण युद्ध में इसलिए नहीं बदली, क्योंकि भारतीय सेना ने मजबूत तैयारी कर रखी थी, जिसे दुश्मन सेना ने भी मान्यता दी।" उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है यानि 1962 के युद्ध के बाद जो स्थिति थी वह कायम है। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा, "सैनिकों को इस तरह की क्रूरता के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रत्यक्ष टकराव फिर से होंगे।" उन्होंने कहा कि युद्धक्षेत्र इंस्टाग्राम, फेसबुक या तस्वीरों की दुनिया नहीं है। युद्धक्षेत्र बेहद क्रूर होता है। उन्होंने कहा कि गलवान में सैन्य झड़प के बाद की स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, जिसमें बड़े बदलाव और सुधार लागू किए जा रहे थे, जबकि सभी मौसमों और परिस्थितियों में अटूट प्रतिबद्धता और अथक तीव्रता के साथ प्रशिक्षण जारी रहा। ब्रिगेडियर शेखावत ने कहा, "बख्तरबंद वाहन, टैंक, नये शामिल किए गए वाहन, घोड़े और विमान, हर संभव साधन का इस्तेमाल किया गया। सीमा पर हथियारों और उपकरणों को उन्नत और मजबूत किया गया।" उन्होंने कहा कि वहां का इलाका और मौसम दुश्मन से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था।

सर्वे में बढ़त की खबरों के बीच हत्या, बांग्लादेश के हिंदुओं में भय का माहौल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले एक हिंदू व्यापारी की निर्मम हत्या और चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में उसी दल और गठबंधन की बढ़त की खबरों ने वहां के हिंदुओं को भीतर तक झकझोर दिया है, जिनके पिछले शासनकाल के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार, पलायन और भय का काला दौर देखा गया था। यादों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि वर्तमान घटनाओं और राजनीतिक संकेतों ने फिर वही डर जगा दिया है कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। हम आपको बता दें कि 9 फरवरी की रात मयमनसिंह जनपद के दक्षिणकांदा गांव में 62 वर्ष के चावल व्यापारी सुषेन चंद्र सरकार की निर्मम हत्या कर दी गयी। हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर उन्हें दुकान के भीतर लहूलुहान छोड़ा, शटर गिराया और लाखों टका लेकर फरार हो गये। जब परिवार ने खोजबीन की तो वह खून से सने मिले। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत बताया। उनके पुत्र सुजन सरकार का कहना है कि पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी हत्या की गयी और धन लूटा गया। सुजन सरकार ने हत्यारों की शीघ्र पहचान कर उन्हें दंडित करने की मांग की है। हम आपको याद दिला दें कि इसी क्षेत्र में एक अन्य हिंदू युवक दिपु चंद्र दास की भी भीड़ ने पीटकर हत्या कर उसे जला दिया था। इन घटनाओं ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है? देखा जाये तो पिछले एक वर्ष में हत्या, आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़, जमीन कब्जाने और झूठे आरोपों के सहारे भीड़ को उकसाने की घटनाएं बढ़ी हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि राजनीतिक बदलाव के बाद अल्पसंख्यकों पर दबाव तेज हुआ है। भारत ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि बार बार हो रहे हमलों को निजी झगड़ा या साधारण विवाद बताकर टालना दोषियों का हौसला बढ़ाता है। भारत का कहना है कि ऐसे माहौल से भय और असुरक्षा फैलती है। हम आपको बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में 300 में से 299 सीटों पर मतदान होगा और साथ में जनमत संग्रह भी होगा। प्रचार अवधि समाप्त हो चुकी है। इस बार अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गयी, जिसका शेख हसीना ने विरोध किया है। वह इस समय भारत में निर्वासन में हैं और उनके विरुद्ध मृत्यु दंड का आदेश भी सुनाया जा चुका है। उनके करीबी और पूर्व वित्त मंत्री हसन महमूद ने चुनाव को पूर्व नियोजित बताते हुए कहा है कि पूरी प्रक्रिया एक खास सोच को सत्ता में बनाये रखने के लिए गढ़ी गयी है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समाज से बहिष्कार की अपील करते हुए यह भी दावा किया है कि वर्तमान अंतरिम सरकार बाहरी असर में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेख हसीना सुरक्षित हैं और जल्द ही लौटेंगी।

'वंदे मातरम्' को लेकर नया निर्देश:

गृह मंत्रालय ने तय किए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को वंदे मातरम के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाना चाहिए और इसके बजने के दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में लिखा था और 1950 में अपनाया गया था। अब पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक पुरस्कार समारोहों और राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित होने वाले सभी अन्य कार्यक्रमों में उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, हालांकि इस दौरान खड़े होना अनिवार्य नहीं है। और इसके सभी छह श्लोक बजाए जाएंगे, जिनमें वे चार श्लोक भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। पहले, जन गण मन राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल परिभाषित नहीं था। इस निर्णय का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मानपूर्वक पालन को

औपचारिक रूप देना और आधिकारिक समारोहों, विद्यालयों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह कदम संसद में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व पर हुई बहसों के बाद राष्ट्रीय प्रतीकों को लोकप्रिय बनाने और उन पर जोर देने के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है और यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ताधारी सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच विवाद का मुख्य कारण भी बन गया था। इस निर्देश और उन चार श्लोकों को शामिल करने से विवाद खड़ा होने की संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल इस मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी।

संपादक की कलम से

भारत सरकार द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियमों की घोषणा एक साहसिक और आवश्यक कदम के रूप में देखा जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने सूचना की विश्वसनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा को चुनौती दी है। इसी को देखते हुए सरकार ने तीन घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने और एआई-निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाने को अनिवार्य किया है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करता है।आज के डिजिटल युग में सूचना की रफ्तार इतनी तेज है कि झूठी या भ्रामक सामग्री केवल कुछ मिनटों में फैल सकती है। डीपफेक और एआई-निर्मित वीडियो या चित्र विशेष रूप से खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता का भ्रम पैदा कर सकते हैं और सामाजिक या राजनीतिक तनाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए चेतावनी का काम करता है।हालांकि, नियमों के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। प्लेटफॉर्म्स को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम होना होगा, बल्कि हर सामग्री का मूल्यांकन करने और सही लेबल लगाने की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही, उपयोगकर्ताओं की डिजिटल स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा।फिर भी, यह कदम डिजिटल दुनिया में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जब एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक तेजी से समाज के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो उसके उपयोग के नियम और पारदर्शिता की स्पष्टता अनिवार्य हो जाती है। सरकार की यह पहल एक संदेश देती है कि तकनीक की शक्ति तभी उपयोगी है जब उसका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। कहा जा सकता है कि एआई और डिजिटल मीडिया के भविष्य में नियमों और पारदर्शिता का यह नया ढांचा न केवल सामाजिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और उपयोगकर्ताओं के लिए जवाबदेही का भी नया मानक स्थापित करेगा। यह समय की मांग है कि हम तकनीक की शक्ति को नियंत्रित करने के साथ-साथ उसका जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करें।

राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र को घेरा,
उठाया देशहित का सवाल

लोकसभा में राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया, ऊर्जा और वित्त पर बाहरी दबाव स्वीकार किया और 'भारत माता को बेचा'। शुल्क वृद्धि और अमेरिकी आयात बढ़ने पर भी उन्होंने तीखा विरोध जताया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या उसे भारत को बेचने में शर्म नहीं आती? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रभावी रूप से भारत माता को बेच दिया है। लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि विश्व एक वैश्विक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का शस्त्रीकरण हो रहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से शस्त्रीकरण करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप स्वयं मानते हैं कि हम एक वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं – एक महाशक्ति का युग समाप्त हो गया है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हो रहा है। फिर भी, इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी, आपने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे हम प्रभावित होते हैं। उन्होंने दावा किया कि जब अमेरिका कहता है कि हम किसी विशेष देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हो रही है – ऊर्जा का ही हमारे विरुद्ध दुरुपयोग हो रहा है। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूँ कि आपने भारत के हितों से समझौता किया है। क्या आपको अपने इस कृत्य पर कोई शर्म नहीं है? ऐसा लगता है जैसे आपने 'भारत माता' को बेच दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी पर एक और हमले में गांधी ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को बेच देंगे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की आँखों में स्पष्ट भय दिखाई दे रहा था और "एपस्टीन फाइलों" को गुप्त रखे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने गुप्त दबावों की ओर इशारा किया। राहुल गांधी ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में भारत को नहीं बेचेंगे। आप जानते हैं उन्होंने भारत को क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पर शिकंजा कस रखा है... हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। दो बातें हैं - पहली, एपस्टीन का मामला। 30 लाख फाइलें अभी भी बंद हैं। शुल्क को लेकर चिंता जताते हुए गांधी ने कहा कि औसत शुल्क लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है, यानी छह गुना वृद्धि। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि भारत में अमेरिकी आयात 46 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 146 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। उन्होंने इस स्थिति को "बेतुका" बताते हुए आरोप लगाया कि भारत बिना किसी ठोस प्रतिबद्धता के प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब डॉलर का आयात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा, आपने शुल्क पर क्या किया है? पहले औसत शुल्क लगभग 3 प्रतिशत था। अब यह बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है - छह गुना वृद्धि। साथ ही, भारत में अमेरिकी आयात 46 अरब डॉलर से बढ़कर 146 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यह बेतुका है।

रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला,
बोले– संसद में बचकाना व्यवहार अस्वीकार्य

टीवी भारतवर्ष तेलंगाना

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा को लेकर चल रहे विवाद के बीच जमकर निशाना साधा और उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को "राजनीतिक हथियार" के रूप में इस्तेमाल न करने को कहा। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए रिजिजू ने उनसे बच्चों जैसा व्यवहार न करने को कहा। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को सबक नहीं सिखा सकता। मुझे समझ नहीं आता कि वे किस दुनिया में रहते हैं। कौन सी विचारधारा उनके कार्यों को प्रेरित करती है? रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को उन्हें समझाना चाहिए कि संसद इस तरह काम नहीं कर सकती। यहां बच्चों जैसा व्यवहार न करें। हमारा देश विशाल है और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी सुरक्षा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। हालांकि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में गांधी की टिप्पणियां सच थीं। वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि वे इस मुद्दे पर इतना डर क्यों दिखा रहे हैं। वे इन सब बातों से क्यों डर रहे हैं? हम नहीं डरते। वे जो चाहें करें। हमने संसद के अंदर और बाहर जो कुछ भी कहा है, वह स्पष्ट और सटीक है। हम इस मुद्दे पर पूरी तरह से कायम हैं। रहुल गांधी द्वारा लोकसभा में जनरल नरवणे के संस्मरण, 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' का हवाला देने के प्रयास के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने बजट सत्र के दौरान चीन के साथ 2020 के गतिरोध को चर्चा में घसीटा।

अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा या साजिश?
भतीजे रोहित पवार ने VSR कंपनी पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने बुधवार को अपने चाचा अजित पवार के विमान हादसे से जुड़े हालातों पर फिर से संदेह जताया और इसे साजिश बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने विमानन कंपनी पर सवाल उठाए। एरो कंपनी के संचालक मनोज पवार का हवाला देते हुए एनसीपी (एसपी) नेता ने संकेत दिया कि विमान हादसा बारामती में कम दृश्यता के कारण नहीं हुआ था। रोहित पवार ने कहा अजित पवार महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक नेता थे। महाराष्ट्र के लोगों को उनके विमान हादसे पर संदेह है। हमने पिछले 13 दिनों में अपने सूत्रों के आधार पर कुछ जानकारी जुटाई है। हम इस मामले को लेकर भावुक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज पवार एरो कंपनी के संचालक हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनोज पवार ने अजित दादा के सहायक कर्मचारियों, महाराष्ट्र विमानन निदेशक और पायलट सहित एक समूह में कहा कि दृश्यता ठीक है। वीएसआर के मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा, 'विमान का रखरखाव ठीक था, पायलट अनुभवी थे और दुर्घटना संभवतः दृश्यता की समस्या के कारण हुई।' इस बयान में कुछ गड़बड़ है। पवार ने मांग की कि जांच एजेंसियां तकनीकी लॉग और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करें ताकि उड़ान से पहले उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की पहचान की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, 'दादा को ले जा रहे विमान से एक अलग तरह की आवाज आ रही थी और वह नीची उड़ान भर रहा था।' जब विमान स्टॉल हुआ, तो स्टॉल मैन्युअल भी हो सकता है, या कोई यांत्रिक खराबी हो सकती है। पायलट या किसी भी व्यक्ति की यही प्रतिक्रिया होती, जैसा कि पायलट पाठक की थी। विमान का रखरखाव प्रतिदिन करना होता है। तकनीकी लॉग पर किसने हस्ताक्षर किए? हम मांग करते हैं कि जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाए। उन्होंने बारामती में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की कमी को भी उजागर किया और कहा कि 2023 में इसी तरह की विमान दुर्घटना की जांच समय पर की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 2023 में मुंबई में हुए विमान हादसे से पता चलता है कि रनवे समतल था। बारामती में आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) नहीं है; मुंबई में आईएलएस होने के बावजूद भी विमान दुर्घटना हुई। आईएलएस न होने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि 2023 के हादसे में भी वीएसआर का विमान इस्तेमाल हुआ था। अगर हमें पहले से (जांच की) जानकारी होती, तो अजित पवार शायद इस हादसे का शिकार नहीं होते। आज भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, नेता हों या कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर दिल्ली आए हों, उन्होंने भी वहां वीएसआर के विमान का इस्तेमाल किया था। वीएसआर द्वारा विमानों के रखरखाव का तरीका गलत है। इसी वजह से 2023 में मुंबई में और अजीत दादा के साथ हादसा हुआ। इसलिए, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आपात स्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कृपया किसी भी वीएसआर विमान का इस्तेमाल न करें।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों से बिना गारंटी लोन लेना हुआ आसान

बिना गारंटी लोन पर RBI का अहम निर्णय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऋण नियमों में व्यापक संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित बदलावों के तहत कुल परिसंपत्तियों में असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज की सीमा को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की अनुमति देने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को अधिक लचीलापन देना और छोटे उधारकर्ताओं तक ऋण की पहुंच आसान बनाना है।आरबीआई द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, केंद्रीय बैंक व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाने, असुरक्षित कर्ज की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने और ऐसे ऋणों की कुल सीमा में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है। इससे यूसीबी को अपने ग्राहकों, खासकर छोटे व्यापारियों और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।केंद्रीय बैंक ने बयान में स्पष्ट किया कि कुल परिसंपत्तियों में असुरक्षित कर्ज की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस सीमा से अधिक अतिरिक्त असुरक्षित ऋण केवल प्राथमिकता क्षेत्र के पात्र ऋणों के लिए ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपये की मौद्रिक सीमा तय की गई है।इसके अलावा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इससे घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ग्राहकों को अधिक वित्तीय सुविधा मिल सकेगी।मसौदे में तीसरे और चौथे स्तर की शहरी सहकारी समितियों के लिए आवास ऋण की अवधि और स्थगन (मोरेटोरियम) संबंधी आवश्यकताओं को नियामकीय प्रावधानों से मुक्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि इससे आवास क्षेत्र में ऋण वितरण को बढ़ावा मिलेगा और बैंकों को संचालन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।आरबीआई ने इस महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण मानदंडों की समीक्षा की घोषणा की थी। मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि यूसीबी की प्रबंधन और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए 'मिशन-सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण)' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।मल्होत्रा ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े 1.4 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना है, ताकि बैंकिंग संचालन, जोखिम प्रबंधन और तकनीकी दक्षता को बेहतर बनाया जा सके।आरबीआई ने मसौदा प्रस्ताव पर वित्तीय संस्थानों, संबंधित पक्षों और आम जनता से 4 मार्च, 2026 तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित बदलावों से शहरी सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता में वृद्धि होगी और ग्राहकों, विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी। हालांकि, असुरक्षित ऋण की सीमा बढ़ने से जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, जिसे ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।

भारत के साथ मैच से पहले बिगड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स के बोल

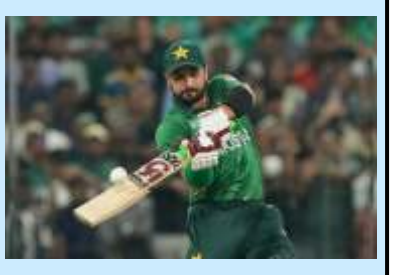

टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है. इस मैच से पहले साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक ने सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को चेतावनी दी है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार साहिबज़ादा फरहान ने वादा किया है कि जब 15 फरवरी को कोलंबो में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी तो उनकी टीम भारत के खिलाफ बिल्कुल अलग मानसिकता के साथ खेलेगी. फरहान ने अपने साथी उस्मान तारिक के साथ भारत को कड़ी टक्कर देने का भरोसा जताया है और IND vs PAK मुकाबले से पहले सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी को चेतावनी दी है. पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजों पर उन्हें खेलने को लेकर अतिरिक्त दबाव होगा. हाल ही में जिनकी गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठे थे, उस्मान ने अमेरिका के खिलाफ 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. अपने एक्शन को लेकर भारतीय प्रशंसकों के बीच हो रही चर्चा पर पूछे गए सवाल के जवाब में उस्मान ने कहा कि वह केवल अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं और बाहरी शोर से प्रभावित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि उन पर अतिरिक्त दबाव होगा. क्योंकि जिस तरह वे इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, अगर वे इस तरह आपत्ति जता रहे हैं, तो इससे लगता है कि शायद उन पर अतिरिक्त दबाव होगा.

तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को लेकर अहम अपडेट दिया है।

ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रनों से हराया, जम्पा ने झटके 4 विकेट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 14वां मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच खेला गया. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 67 रनों से जीत हासिल की. टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके जवाब में उतरी आयरलैंड की टीम 17वें ओवर में 115 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे. हेड के बल्ले से केवल 6 रन आए. उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 रन था. इसके बाद ग्रीन और इंग्लिश के बीच अच्छी साझेदारी हुई लेकिन 5वें ओवर में ग्रीन आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका 69 के स्कोर पर लगा जब इंग्लिश 37 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन इसके बाद आयरलैंड के गेंदबाजों ने दम दिखाया और ग्लेन मैक्सवेल को सस्ते में आउट कर दिया. मैक्सवेल के बल्ले से केवल 9 गेंदों पर 9 ही रन आए. हालांकि, इसके बाद मार्कस स्टोइनिस और मैट रेनशॉ ने अच्छी बल्लेबाजी की. स्टोइनिस ने 29 गेंद में 45 रन बनाए. जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए.

दो सुपर ओवर के बाद फैसला, साउथ अफ्रीका ने जीता रोमांचक मैच

साउथ अफ्रीका ने टी-20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को डबल सुपर ओवर में हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में टूर्नामेंट के इतिहास का पहला डबल सुपर ओवर देखने को मिला। ग्रुप-डी के इस मैच के दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने 6 गेंदों पर 23 रन बनाकर अफगानिस्तान को 24 रन का लक्ष्य दिया। टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम ने दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद नबी का विकेट गंवा दिया। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने तीसरी, चौथी व पांचवीं गेंद पर लगातार तीन छक्के जड़ दिए, लेकिन आखिरी बॉल पर आउट हो गए। इससे पहले दूसरे सुपर ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर ने तीन सिक्स लगाकर साउथ अफ्रीका को 23 रन तक पहुंचाया था। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने फजलहक फारूकी की बॉल पर सिक्स लगाकर स्कोर बराबर किया था। अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। ओवर की पहली ही गेंद पर कागिसो रबाडा ने नो-बॉल फेंकी। उस पर कैच भी हुआ, लेकिन बल्लेबाज आउट नहीं हुए और फ्री-हिट मिल गई। इसके बाद एक वाइड और फिर फ्री-हिट ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बढ़ा दिया। 19.2 बॉल पर नूर अहमद ने सिक्स लगाकर मुकाबला अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया। अब 4 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। अगली गेंद डॉट रही, लेकिन 19.4 पर फिर नो-बॉल हो गई, जिस पर नूर ने दो रन ले लिए और टीम जीत के बेहद करीब पहुंच गई। इसके बाद आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर नूर ने लॉन्ग-ऑफ की तरफ शॉट खेला और आसान दो रन का मौका बन गया, लेकिन यहीं मैच पलट गया। दूसरा रन लेते समय फजलहक फारूकी धीमे पड़ गए। रबाडा ने तेजी से गेंद उठाकर बेल्स उड़ा दीं। रिप्ले में साफ दिखा कि फारूकी का बैट हवा में था, जिसके चलते उन्हें रन-आउट दे दिया गया।

भानुका राजपक्षे ने भारतीय क्रिकेटरों के बैट पर दिए बयान पर दी सफाई

भानुका राजपक्षे ने भारतीय क्रिकेटरों के बैट पर दिए बयान पर दी सफाई, कहा- मेरा मकसद तारीफ करना थानई दिल्ली: श्रीलंका के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने भारतीय क्रिकेटरों के बैट को लेकर दिए गए अपने कथित बयान पर सफाई जारी की है। हाल ही में एक न्यूज़वायर रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया था कि भारतीय क्रिकेटर जो बैट इस्तेमाल करते हैं, वे अन्य खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता के होते हैं और ऐसा लगता है मानो उन पर रबर की एक परत चढ़ी हो। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई।हालांकि, विवाद बढ़ने पर राजपक्षे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने लिखा, "हाल ही में मेरे एक इंटरव्यू के बारे में मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। मैंने जो कहा उसका कुछ और मतलब निकाल लिया गया और शायद ट्रांसलेशन की गड़बड़ी की वजह से उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया।"राजपक्षे ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भारतीय बल्लेबाजों या उनके उपकरणों पर सवाल उठाना नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रणाली की सराहना करना था। उन्होंने कहा, "मेरा मकसद भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करना था। भारतीय क्रिकेट काफी एडवांस हो चुकी है। उनका सिस्टम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके इक्विपमेंट सब आला दर्जे के हैं। उनके बैट निर्माता वर्ल्ड क्लास के हैं।"श्रीलंकाई बल्लेबाज ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपनी बात और बेहतर संदर्भ में रखनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा, "मुझे लगता है कि मैं और बेहतर कॉन्टेक्स्ट के साथ अपनी बात रख सकता था।"राजपक्षे ने अंत में भारतीय क्रिकेटरों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा, "भारतीय क्रिकेटरों के प्रति मेरे मन में सिर्फ सम्मान है और कुछ नहीं।"

डीएनए जांच में हुआ बड़ा खुलासा

हिटलर की महिलाओं से दूरी की वजह सामने आई

बीबीसी हिस्ट्रीएक्स्ट्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया है कि कहां से हिटलर का डीएनए लिया गया और टेस्ट के बाद जो परिणाम सामने आए उससे क्या खुलासा हुआ है. टूरी किंग और एलेक्स जेके ने एडॉल्फ हिटलर के डीएनए के नमूने का अध्ययन किया और इस विश्लेषण से जुड़े जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे.

हिटलर के डीएनए टेस्ट से हुए हैरान करने वाले खुलासे (Photo - X)

हिटलर ने शादी नहीं की थी. इस बारे में कई अफवाहें और कहानियां हैं. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों में ऐसी चर्चाएं होती रहती थीं कि हिटलर महिलाओं से दूर भागता था. उसमें कुछ ऐसी कमी थी कि उसने शादी नहीं की.

खासकर उसकी शारीरिक कमियों को लेकर हमेशा से अटकलें लगाई जाती रही हैं. अब हिटलर के डीएनए टेस्ट से ऐसे खुलासे हुए हैं, जो बताते हैं कि इन चर्चाओं की वजह बेबुनियाद नहीं थी. हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 की दोपहर को अपने बर्लिन बंकर में आत्महत्या कर ली थी. हिटलर की मौत के 80 साल बाद 'Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator' नाम की डॉक्यूमेंट्री के जरिए उसके डीएनए टेस्ट के परिणाम की जानकारी पहली बार सार्वजनिक की गई. बीबीसी हिस्ट्रीएक्स्ट्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया है कि कहां से हिटलर का डीएनए लिया गया और टेस्ट के बाद जो परिणाम सामने आए उससे क्या खुलासा हुआ है. टूरी किंग और एलेक्स जेके ने एडॉल्फ हिटलर के डीएनए के नमूने का अध्ययन किया और इस विश्लेषण से जुड़े जो परिणाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे. डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि डीएनए के टेस्ट के लिए पहला कदम यह पुष्टि करना था कि रक्त का नमूना वास्तव में हिटलर का ही था. ⊙

छोटा निकला सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह

सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति (जूपिटर) पहले के अनुमान से थोड़ा छोटा निकला है. नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने अब तक का सबसे सटीक माप लिया है, जिससे पता चला कि इसका आकार और आकृति पहले बताए गए साइज से कुछ अलग है.

यह जानकारी ग्रह के अंदरूनी ढांचे को समझने और सौरमंडल के निर्माण की कहानी जानने में बहुत मदद करेगी. बृहस्पति पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा चपटा (फ्लैट) है. नए आंकड़ों से पता चला कि यह पहले सोचे से थोड़ा ज्यादा ऑचपटा है. ⊙

जीवनशैली में बदलाव के लिए उठाया कदम

एक साल के लिए बेडरूम में बंद हुआ एक शख्स

एक शख्स ने अपनी जीवनशैली में बेहतर बदलाव लाने के लिए एक साल तक अपने बेडरूम में ही बंद रहने और बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखने की योजना बनाई है. वह कमरे में बंद हो चुका है.

49 साल का ये शख्स इस दौरान अपने परिवार वालों से भी नहीं मिलेगा. 10 जनवरी को यूटा के स्किप बॉयस ने अपनी पत्नी और बेटी को अलविदा कहा और अपने बेडरूम के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया . इसके साथ ही उसने अपना "एकांतवास का वर्ष" प्रोजेक्ट शुरू किया. उनकी योजना कुल 365 दिनों तक वहीं रहने की है. इस पूरे अनुभव को वह यूट्यूब पर लाइव

स्ट्रीम करेंगे. ऑडिटिसेंट्रल के मुताबिक, कमरे के अंदर अकेले रहना का नियम सीधा-सादा है. स्किप बॉयस ने बताया था कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा और लाइवस्ट्रीम 24/7 चालू रहेगा. मैं बाहर से कोई मनोरंजन के उपाय अंदर नहीं लाऊंगा. मैं बाहर से किसी भी तरह के बातचीत में हिस्सा नहीं लूंगा. ⊙

महिला का वीडियो हो रहा है वायरल

कचरा फेंकने के लिए पोर्टर की बुकिंग

लखनऊ को यूं ही नहीं नवाबों का शहर कहा जाता है. यहां के रहने वाले लोगों में थोड़ी ही लेकिन नवाबी होती जरूर है. ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह इसका प्रमाण दे रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला की रईसी देखने को मिल रही है. उसने ऑनलाइन पोर्टर बुक किया होता है और जब राइडर उसे लेकर जाता है, तो वह खुद दुविधा में पड़ जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि महिला ने पार्सल में सामान नहीं बल्कि घर का कचरा भरा होता है, जिसे फेंकने के लिए उसने राइड बुक किया था. पोर्टर से सामान भेजने के लिए एक महिला ने हमेशा की तरह ऑनलाइन पोर्टर बुक करती है. इसके बाद राइडर

वहां पहुंचता है और पूछता है पेमेंट हो गया है? तो महिला बोलती है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दी है' और पार्सल राइडर को दे देती है. लेकिन पार्सल को डिलीवर करने की लोकेशन पर जब ड्राइवर पहुंचता है तो, वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है.

महिला को कॉल करके पूछता है कि 'पार्सल किसको देना है? इसके बाद महिला जो बोलती है, वह उसे हैरान कर देता है. वह बोलती है कि भेया, किसी को देनी नहीं है फेंक दीजिए. राइडर ने अपने साथ हुए इस घटना का दूसरा वीडियो भी बनाया. कस्टमर से ये क्या बात हुई? पूछने के बाद पोर्टर वाला कूड़ा फेंक देता है और बोलता है कि 'पोर्टर इसीलिए चला रहा हूं, ताकी दूसरों का कूड़ा फेक सकूं. ⊙

Lahore 1947 की रिलीज डेट का एलान!

स्वतंत्रता दिवस पर होगा धमाका

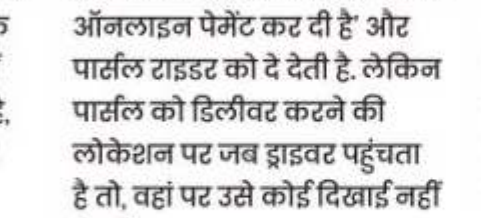

सनी देओल के फैंस के लिए बड़ी खबर है! आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी महत्वाकांक्षी पीरियड ड्रामा फिल्म 'लाहौर 1947' की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 13 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो कि स्वतंत्रता दिवस के हफ्ते का बड़ा धमाका होने वाली है। इस फिल्म के साथ पहली बार आमिर खान (निर्माता), राजकुमार संतोषी (निर्देशक) और सनी देओल (अभिनेता) की तिकड़ी एक साथ काम कर रही है। आमिर खान कहते हैं, "यह धरमजी की पसंदीदा स्क्रिप्ट में से एक है, और मुझे बहुत खुशी है कि वह यह फिल्म देख पाए।" सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा और करण देओल अभिनीत, एआर रहमान द्वारा संगीत और जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ, 'लाहौर 1947' सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की मौजूदा सफलता के बाद अगला प्रोजेक्ट है। फिल्म के रिलीज की घोषणा के साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माता आमिर खान फिल्म के शीर्षक से 'लाहौर' शब्द हटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण वर्तमान राजनीतिक माहौल और एक पाकिस्तानी शहर के नाम को फिल्म के टाइटल में रखने को लेकर संवेदनशीलता बताया जा रहा है। हालांकि, निर्देशक राजकुमार संतोषी इस बदलाव के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा: "शीर्षक बदलना एक तरह का तुष्टीकरण होगा, जिसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैंने इस फिल्म के लिए 20 साल इंतजार किया है। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और सनी देओल इस रोल के लिए एकदम फिट हैं।" 'गदर 2' और 'जाट' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद सनी देओल 'लाहौर 1947' को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आमिर खान ने भी बताया कि यह उनके पिता धर्मेंद्र की पसंदीदा स्क्रिप्ट्स में से एक थी और वे खुश हैं कि वे इसे पर्दे पर उतार रहे हैं।

लखनऊ विकास को रफ्तार: नाइट सफारी के लिए 207 करोड़, मिल्क कंपनी और कैंसर संस्थान को हरी झंडी

योगी सरकार ने लखनऊ के विकास के लिए बजट में करीब 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुकरैल नाइट सफारी को 207 करोड़, कैंसर संस्थान को 315 करोड़ और राष्ट्र प्रेरणा स्थल को 50 करोड़ रुपये दिए गए। डिफेंस कॉरिडोर, मिल्क कंपनी और शहरी विकास से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन बजट में राजधानी लखनऊ को विशेष प्राथमिकता देते हुए लगभग 1000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरैल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2027 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,510 करोड़ रुपये है। पिछले बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। सरकार का दावा है कि इसे सिंगापुर की विश्व प्रसिद्ध नाइट सफारी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे लखनऊ को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।स्वास्थ्य क्षेत्र में जियामऊ स्थित कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उन्नत उपचार सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए लखनऊ और पीलीभीत में संचालित दो राजकीय औषधि निर्माण शालाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड जारी किया गया है। वहीं, लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।महिला सामर्थ्य योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना की योजना है। गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में कार्य शुरू हो चुका है, जबकि प्रयागराज और लखनऊ में कंपनियों का गठन किया जाएगा। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को भी अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए एमओयू किए जा चुके हैं। इस परियोजना में 35,280 करोड़ रुपये के निवेश और 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके तहत लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना लॉन्च की गई है। मेरठ में 35 वर्ष और आगरा में 33 वर्ष बाद आवासीय योजनाएं शुरू हुई हैं, जबकि बुलंदशहर में पहली बार औद्योगिक योजना लागू की गई है।पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के तहत अयोध्या, मथुरा और लखनऊ सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐशबाग, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य जारी है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

रहीमाबाद में बचपन की सहेलियों की मौत

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में हादसा हो गया है। यहां मनकोटी गांव के बाहर ट्रेन पटरी पर बचपन 2 सहेलियां कट गईं। एक लड़की की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। वह आज ही सुबह मायके आई थी। कुछ देर बाद दोनों की डेडबॉडी ट्रेन पटरी पर मिली। ट्रेन से लड़कियों के कटने की सूचना पर गांववालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना बेलवा रेलवे फाटक के पास की है। मृतक सहेलियां रहीमाबाद के मनकोटी गांव की थीं। गांववालों के अनुसार, वे दोनों हरपल साथ ही रहती थीं। आज दोनों की साथ ही मौत हो गई। रहीमाबाद थाना पुलिस के अनुसार, मृतक युवतियों की उम्र 20 और 23 साल है। 20 वर्षीय शशि पुत्री अशर्फी लाल और 23 वर्षीय नीतू पुत्री बुद्धा की मौत हुई। इन दोनों की ट्रेन से कटने की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे ट्रैक पार रही थीं लेकिन दूसरे एंगल पर भी जांच की जा रही है। नीतू के मायके आने के बाद दोनों घर से निकलीं और ट्रेन से टकराकर उनकी मौत हो गई। आशंका है कि दोनों ने सुसाइड किया होगा। बहरहाल जांच और पूछताछ के बाद पता चल सकेगा कि आखिर यह हादसा था या सुसाइड। घरवाले कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वहीं, पड़ोसियों का कहना है कि नीतू और शशि बचपन से ही हरपल साथ रहती थीं। नीतू की शादी 6 महीने पहले हुई थी। उसका पति इशू चंडीगढ़ में रहकर काम करता है। नीतू आज ही अपने मायके आई हुई थी। अपनी सहेली शशि के साथ गांव के बाहर निकली। दोनों बिना बताए ही निकलीं और पता नहीं क्यों दोनों ने मौत चुन ली? यह भी हो सकता है कि दोनों टहलने गई हों और उनके साथ हादसा हो गया है।

लखनऊ के यहियागंज में किराना दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के यहियागंज इलाके में मंगलवार देर रात मुजम्मिल की किराना दुकान में अचानक आग लग गई। आग फैलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग गली में निकल आए। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखा सारा सामान धू-धूकर जलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुकान से 10 फीट तक लपटें उठ रही थीं।स्थानीय लोगों ने तुरंत चौक फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली कराया गया ताकि किसी तरह का बड़ा नुकसान न हो।सौभाग्यवश, आग लगने के समय दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया।प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर विभाग और बिजली विभाग की टीम इसके कारणों की पुष्टि के लिए जांच कर रही है।दुकानदार मुजम्मिल ने बताया कि दुकान में राशन और अन्य किराना सामान रखा था, जिसका नुकसान भारी हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उनका रोज़गार है और आग लगने से उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि आग पर नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि दुकान का इलाका संकरा है और आस-पास कई अन्य दुकानों में भी सामान रखा हुआ था। आग फैलने से बचाने के लिए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई।स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद करते हुए आग बुझाने में सहयोग किया। अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई की वजह से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।यह घटना यहियागंज क्षेत्र में आग सुरक्षा और सावधानी के महत्व को फिर से उजागर करती है। फायर विभाग ने दुकानदारों और नागरिकों से शॉर्ट सर्किट और आग से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है।लखनऊ फायर ब्रिगेड की तत्परता और स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण यह घटना बड़ी त्रासदी में बदलने से बच गई।

लखनऊ: वेव मॉल की जांच में खुलासा, पार्किंग एरिया में 50 अवैध निर्माण

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ: वेव मॉल की पार्किंग में 50 से अधिक अवैध दुकानें, एलडीए ने की नपाईलखनऊ। राजधानी के विभूतिखंड स्थित वेव मॉल में पार्किंग क्षेत्र में 50 से अधिक अवैध दुकानों के निर्माण का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम बुधवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की नपाई कर जांच शुरू की।जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी और रवि नंदन के नेतृत्व में टीम ने मॉल परिसर और उसके चारों ओर बनी चार मंजिला इमारत की पैमाइश की। वर्ष 2004 में निर्मित इस मॉल के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप है कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण (डेविएशन) किया गया है।कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए मॉल परिसर में संचालित अस्थायी दुकानों को अवैध बताते हुए घोषणा की। टीम ने मौके पर उपलब्ध मानचित्र का मिलान कर निर्माण की स्थिति का आकलन किया।जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि डेविएशन की शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई है। फिलहाल फ्लोर-वाइज स्वीकृत प्लान मंगाया जा रहा है। इंजीनियरों की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रारंभिक जांच में कॉलम और बाउंड्री से जुड़े कुछ मामूली डेविएशन चिन्हित किए गए हैं।एलडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर नोटिस जारी कर अतिरिक्त निर्माण हटाने का निर्देश दिया जाएगा। आवश्यक होने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से नियमानुसार कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराने का विकल्प भी दिया जाएगा।

लखनऊ हादसा: ट्रैक्टर से टक्कर, युवक की जान गई, 3 की हालत गंभीर

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हरदोई रोड स्थित अंधे की चौकी के पास मछली मंडी गेट के सामने ईंटों से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारुति वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को वैन से निकालकर तत्काल ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश पटेल ने बताया कि हादसे में घायल संजय सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अन्य घायलों में पप्पू कश्यप, पप्पू सिंह सैगर और हर्ष सिंह शामिल हैं। हर्ष की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि अन्य दो घायलों का भी गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार, मारुति वैन कानपुर देहात के मैथा क्षेत्र से बाराबंकी की ओर जा रही थी, तभी हरदोई रोड पर सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई।

ब्रजेश पाठक और CM योगी ने पंडित दीनदयाल को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की

लखनऊ में भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। इसमें सीएम योगी को पहुंचना था लेकिन वह कैबिनेट बैठक और उसके बाद बजट सत्र के चलते नहीं पहुंच पाए। इसके बाद कार्यक्रम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। उन्होंने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को उत्तर प्रदेश सरकार साकार कर रही है।

सीएम योगी की गैरमौजूदगी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मेयर सुषमा खर्कवाल, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल स्मृतिका वाटिका में आयोजित किया गया। सीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही पंडित दीनदयाल के चित्र पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, एकात्म मानववाद के प्रणेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सशक्त राष्ट्र के निर्माण तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की ज्योति पहुंचाने का उनका संदेश हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। ब्रजेश पाठक ने कहा- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के क्रम में यूपी सरकार हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग कम से कम पंडितजी के एकता, मानववाद के सिद्धांत को जानें, समझें और उसको धरातल पर उतारें। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। पंडितजी ने जनसंघ की स्थापना काल से लेकर अपने सिद्धांतों की बदौलत देश पर नई दिशा देने का काम किया था। आज उसको पूरा करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं।

योगी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश,

अखिलेश यादव बोले- अब इनकी विदाई तय

टीवी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को सत्तारुढ़ भाजपा का विदाई बजट करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा, "यह विदाई बजट है। इसके साथ ही भाजपा की विदाई भी तय है। इसके बाद अब वे लौटने वाले नहीं हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ों से और अपने प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यादव ने कहा, "यह बजट केवल बड़े आकार का है। जनता की भलाई के लिये इसमें कुछ भी नहीं है। अगर बजट आकार में सबसे बड़ा है तो क्या हुआ? उससे गरीब जनता, किसानों तथा नौजवानों को कितना लाभ मिल रहा है।" पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर पिछले बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, "आकार बड़ा है, मगर खर्च कितना किया... अगर हम पिछले बजट से तुलना करें तो जो औसत आ रहा है, उसके मुताबिक यह सरकार 50 प्रतिशत बजट भी खर्च नहीं कर पा रही है।" उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में पिछले बजट में आवंटित धनराशि का सिर्फ 57 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च कर पाई है। सपा प्रमुख ने कहा कि इसके अलावा ग्राम्य विकास में 36 प्रतिशत, पशुधन में लगभग 60 फीसदी, स्वास्थ्य में 58 प्रतिशत, महिला कल्याण में 53 फीसदी और बेसिक शिक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग में सिर्फ 62 प्रतिशत बजट ही खर्च किया जा सका है। अखिलेश यादव यादव ने कहा, "यह तो सरकार की नाकामी है कि जब हम बजट का आकार इतना बड़ा कर रहे हैं लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो किसी भी विभाग में पूरा बजट नहीं खर्च किया जा पा रहा है। अगर महत्वपूर्ण विभागों में ही बजट पूरा खर्च नहीं किया जा पा रहा है तो इसे सरकार की अक्षमता ही कहा जाएगा।" सपा प्रमुख ने दावा किया कि सरकार उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर' (एक हजार अरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो कर रही है लेकिन उसके अनुरूप कदम नहीं उठा रही है। उनके मुताबिक, सरकार कह रही है कि वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा, "वास्तविकता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाना है तो जीएसडीपी को 90 लाख क रोड़ का होना चाहिए। सरकार बताए कि अब जब उसने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहां से बनेगी? अगर हमें 'एक ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनानी है तो विकास दर 30 प्रतिशत होनी चाहिए।" अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार हमेशा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताकर अपनी पीठ थपथपाती है लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये। उन्होंने दावा किया, "पुलिस का हाल तो यह हो गया है कि इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नरम। जब मुकदमे ही नहीं दर्ज होंगे तो अपराध के आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। पहले पुलिस तथा अपराधी दो टीमें होती थीं लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कप्तान है। 'संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर अपराध हो रहे हैं। भाजपा और पुलिस बेईमानी तथा भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं।" उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि लगता तो यह है की बजट बनाते-बनाते और फर्जी आंकड़े दिखा दिखा कर भाजपा के लोग अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं।

कानपुर में दुलारे ज्वेलर्स में IT रेड

टीवी भारतवर्ष कानपुर

कानपुर के लालबंगला स्थित दुलारे ज्वैलर्स में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे आयकर विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। टीम ने दुकान के साथ ही सामने स्थित मकान में भी दस्तावेज खंगालने और पूछताछ की कार्रवाई शुरू की है। हालांकि देर शाम तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्रवाई सर्वे के तहत है या छापेमारी के रूप में की जा रही है। आयकर विभाग की टीम पांच लग्जरी गाड़ियों से पहुंची, जिसके बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। दुकान के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसमें पीएसी के जवान भी शामिल हैं। मुख्य गेट पर सुरक्षा घेरा बनाकर किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री रोक दी गई। अधिकारियों ने दुकान के कर्मचारियों को अंदर ही रोक लिया है। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की दो टीमें दुकान के सामने स्थित घर में भी दस्तावेजों की जांच और पूछताछ कर रही हैं। कार्रवाई एक-दो दिन तक चलने की संभावना है। तथ्यों के आधार पर आगे संयुक्त कार्रवाई की भी तैयारी की जा सकती है।

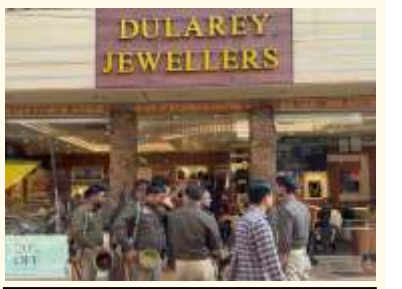

घायल ने कारोबारी से समझौता किया: ड्राइवर ने सरेंडर किया; कानपुर कोर्ट ने नहीं माना आरोपी

टीवी भारतवर्ष कानपुर

कानपुर के लेम्बोर्गिनी केस में बुधवार को यू-टर्न हुआ। पहले कथित ड्राइवर ने दोपहर में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिर मुकदमा दर्ज कराने वाले मो. तौसीफ ने समझौता कर लिया। हालांकि, कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी, उसे आरोपी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं नाम नहीं है। इसलिए उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई। कार अभी थाने में ही रहेगी। इससे पहले ड्राइवर मोहन वकील नरेंद्र कुमार यादव के साथ कोर्ट पहुंचा। मोहन ने कहा कि शिवम मिश्रा की गाड़ी मैं ही चला रहा था। शिवम को दौरा पड़ गया था। उस वक्त मैं घबरा गया था। कुछ समझ नहीं आया। उसी वक्त हादसा हो गया। जब शीशा तोड़ा और दरवाजा खोला गया तो मैं नीचे से निकल गया था। बाउंसर ने शिवम को निकाला था। हादसे के बाद मैं कोने में खड़ा हो गया था। शिवम को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया था। वहीं, बाद शिवम मिश्रा के वकील नरेंद्र कुमार यादव ने कहा- घायल और मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी मो. तौसीफ ने ड्राइवर के साथ समझौता किया है। वादी ने पहचान की है कि गाड़ी मोहन ही चला रहा था। वादी ने कहा है कि वह इस केस में अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने कहा- आरोपी शिवम मिश्रा की ओर से उनके वकील ने जब्त लेम्बोर्गिनी कार को रिलीज कराने के लिए अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान मोहन ने कहा कि गाड़ी वह ड्राइव कर रहा था, जबकि कानपुर पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिवम मिश्रा को ही आरोपी ड्राइवर बताया। बता दें, कि लेम्बोर्गिनी कार ने रविवार को 6 लोगों को कुचल दिया था। इसका वीडियो सामने आया था। पुलिस कमिश्नर ने जांच के हवाले से दावा किया था कि लेम्बोर्गिनी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। शिवम मिश्रा का नाम भी FIR में जोड़ा गया था। केस की जांच कर रहे ग्वालटोली थाने के दरोगा दिनेश कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिवम को आरोपी माना है। सारे सबूत कोर्ट में पेश किए। इससे पहले मंगलवार दोपहर कारोबारी केके मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया था कि हादसे के वक्त बेटा शिवम नहीं, ड्राइवर मोहन कार चला रहा था। शिवम उस वक्त सो रहा था। केके मिश्रा ने कहा था कि हादसे के बाद कार लॉक हो गई थी, जिससे बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी। ठीक होने पर बेटे को लेकर मैं खुद थाने आऊंगा। मीडिया ने पूछा कि पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गाड़ी शिवम चला रहा था। इस पर केके मिश्रा ने जवाब दिया था कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे। हालांकि, पुलिस की जांच में CCTV, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और कई ऐसे अहम सबूत सामने आए। इनसे साफ है कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। हादसा उसी से हुआ था। कार में कोई दूसरा व्यक्ति या ड्राइवर मौजूद नहीं था।

TET अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में TET अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, आदेश की प्रतियां जलाईउन्नाव। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य किए जाने के विरोध में बुधवार शाम जिले के शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार के हालिया आदेश के खिलाफ नारेबाजी की और आदेश की प्रतियां जला कर विरोध जताया। इस मौके पर शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि यह कदम उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के खिलाफ है।प्रदर्शनकारी नेताओं ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार देशभर के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। उनका आरोप है कि यह स्थिति भारत सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधन के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय को यह आदेश देना पड़ा।शिक्षकों का तर्क है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा शर्तें अलग थीं। उस समय नियुक्तियां बीटीसी और बीएड जैसी योग्यताओं के आधार पर की गई थीं। एक प्रदर्शनकारी नेता ने कहा, "जो शिक्षक पिछले 20 से 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनसे अब दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करने को कहा जा रहा है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।" उन्होंने इस फैसले को शिक्षक समाज के आत्मसम्मान पर सीधा आघात बताया।प्रदर्शनकारियों ने जानकारी दी कि इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ऑल इंडिया फेडरेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बातचीत की थी। उनके अनुसार, मंत्री ने संशोधन में कमियों को स्वीकार करते हुए इसे सदन में संशोधित कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि 9 फरवरी 2026 को जारी आदेश में न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की बात कही गई, जिससे शिक्षकों में असंतोष और बढ़ गया।प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने संबंधित आदेश की प्रतियां जलाईं। पुतला दहन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर पुतला नहीं फूंका जा सका। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से एहतियातन बीएसए कार्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात रहा।शिक्षक संगठनों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और पुराने शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की अपील की है। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक नई शर्तों के दायरे में लाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है।शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनके अनुसार यह संघर्ष केवल अधिकारों की रक्षा के लिए है और शिक्षक समाज इसे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेगा।प्रदर्शन ने स्पष्ट कर दिया कि टीईटी अनिवार्यता के लागू होने से लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों में भारी असंतोष है और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि पुराने शिक्षकों को उचित छूट दी जाए।

कानपुर-सागर हाइवे पर एचटी लाइन गिरी

टीवी भारतवर्ष कानपुर

घाटमपुर के टेनापुर मोड़ के पास बुधवार दोपहर कानपुर-सागर हाइवे पर एक डंपर की टक्कर से हाईटेंशन (एचटी) लाइन का बिजली पोल टूटकर गिर गया। इससे हाइवे पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद कराई। यह घटना तब हुई जब फतेहपुर जिले के गौरी जरारा गांव निवासी डंपर चालक रामचंद्र कानपुर से कबरई जा रहे थे। उन्होंने बताया कि टेनापुर मोड़ के पास एक ढाबे पर खाना खाने के बाद जब वह डंपर लेकर आगे बढ़े, तो डंपर का पिछला हिस्सा हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे चलती हुई एचटी लाइन हाइवे पर गिर गई। ग्रामीणों ने तुरंत हाइवे पर वाहनों को रोककर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पतारा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित कर बिजली सप्लाई बंद करवाई।

टीवी भारतवर्ष ,उन्नाव

योगी सरकार की महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी सौगात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 का 10वां बजट पेश किया। नए बजट में 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए और 2 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विधान सभा में अपनी सरकार का 10वां बजट प्रस्तुत किया, जो उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों का प्रतीक भी माना जा रहा है। यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बजट में नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण आवंटन प्रस्तावित किया।मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में विकास को गति देना और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देना है। उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित की गई है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी, बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदलने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस बजट में उन्हीं भावनाओं और प्रतिबद्धताओं को दर्शाया गया है। पिछले नौ वर्षों में राज्य का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ गया है, जो विकास की स्थिर दिशा को दर्शाता है।"मुख्यमंत्री ने इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की क्षमता विकास, किसानों के कल्याण और रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।बजट पेश करने से पहले, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया और पिछले कार्यकाल के दौरान योगी सरकार द्वारा हासिल किए गए उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर किया है और औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण उन्नति की है।सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स में रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधार कर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया था। इस सम्मेलन में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें से चार परियोजनाओं के लिए 16,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा चुका है, जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट का केंद्र बिंदु महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं को सशक्त बनाना और राज्य में व्यापक रोजगार अवसर पैदा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित राशि से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास सुनिश्चित होगा।योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग विशेष रूप से शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में इन क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उत्तर प्रदेश देश में निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन सके और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़े।राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट सत्र को 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलाने की घोषणा की है। इस दौरान विधानसभा में बजट के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी और योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद कहा, "यह बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारी प्रतिबद्धता और विकास की दिशा का प्रतीक है। पिछले 9 वर्षों में हमने प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में सुधार लाने का प्रयास किया है, और यह बजट उसी प्रयास का विस्तार है।"बजट में नई योजनाओं के लिए आवंटित राशि, पूंजीगत व्यय और रोजगार सृजन पर बल देने के कारण यह बजट प्रदेश की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होने की संभावना रखता है।

लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख मिलेंगे

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

बजट के अनुसार अब से लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे। आज बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में राज्य ने चौतरफा विकास देखा है, चाहे वह कानून व्यवस्था को मजबूत करना हो, बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विस्तार करना हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल विकास हो, किसानों की समृद्धि हो या गरीबी उन्मूलन हो। वहीं, लड़कियों के लिए घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि रूपये 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रूपये कर दी गई है। योजना हेतु 750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामूहिक विवाह की राशि दोगुना करने के साथ ही अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

शिविर में बच्चों से दुष्कर्म का आरोप, आशुतोष महाराज ने कोर्ट में दायर की याचिका

टीवी भारतवर्ष प्रयागराज

24 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के 6 दिन बाद आशुतोष महराज ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर से अविमुक्तेश्वरानंद की 2 शिकायतें की थीं। पहली शिकायत में आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखा जाता है। उनसे निजी सेवा, भीड़ जुटाने, कार्यक्रमों और पालकी उठवाने जैसे काम कराए जाते हैं। बच्चों का यौन शोषण होने की भी आशंका है। माघ मेले जैसे बड़े आयोजनों में भी बच्चों से काम कराया गया। यह बाल अधिकार और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। शिविर में अवैध हथियार होने की भी आशंका है। आय से अधिक संपत्ति और कई बैंक खातों की जांच की जानी चाहिए। मुकुंदानंद नाम के व्यक्ति की भूमिका की जांच कराई जाए। दूसरी शिकायत में आशुतोष महराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी लेटरपैड और दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया। कहा कि माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष्पीठ का शंकराचार्य बता रहे। वह "ज्योतिष्पीठ/श्री शंकराचार्य शिविर" के नाम से लेटरपैड और दस्तावेज बनवाकर अफसरों को पत्र भेज रहे। ये लेटरपैड-पत्र फर्जी और भ्रामक हैं। इनसे प्रशासन और आम लोगों को गुमराह किया जा रहा। इन लेटरपैड पर 24 जनवरी, 2026 (माघ शुक्ल पंचमी) की तारीख दर्ज है। इसी तारीख का इस्तेमाल कर "श्री शंकराचार्य शिविर" के नाम से पत्र जारी किए गए, जिनकी वैधता पर सवाल उठाए गए। जब प्रशासन ने आशुतोष महाराज की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने 8 फरवरी को कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने लिखा- मेरे ट्रस्ट की ओर से माघ मेला में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए माता शाकुंभरी देवी का महायज्ञ किया जा रहा है। मेरे शिविर में 2 शिष्य आए, जो नाबालिग हैं। उन्होंने मेरे सामने कई खुलासे किए।

शहरी परिवहन में बड़ा निवेश: इलेक्ट्रिक बस और स्टेशन के लिए 550 करोड़, चार्जिंग सुविधा पर 50 करोड़

यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और बस यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए 400 करोड़ और बस स्टेशनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बस स्टेशनों पर चार्जिंग की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये अलग से दिए जाएंगे। सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा 50 प्रतिशत कम करने के लिए (मुख्यमंत्री की जीरो फैटिलिटी योजना) के लिए भी 50 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए निर्देश दे चुके हैं। इसको देखते हुए ही 50 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा। दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों को भी इस रकम से प्रभावी बनाने में मदद मिलने की बात सरकार ने कही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को भी सशक्त करेगा। ई-बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये मिलने से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा।